>

Title: Need to implement the guidelines of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Madhya Pradesh to facilitate timely payment of wages to workers under the scheme.

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): भारत सरकार की एक अति महत्वपूर्ण योजना मनरेगा है जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा अरबों रूपयों का बजट प्रत्येक राज्य को आबंटित किया जाता है तथा जिन राज्यों में मनरेगा योजना का सुचारू संचालन हुआ है वहां के निवासियों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ है। जिसका ज्वलंत उदाहरण मेरे संसदीय क्षेत्र माँ जालपा की नगरी राजगढ़ का है। जहां के ग्रामीण लोग पूर्व में एक वर्ष में लगभग आठ महीने राजस्थान के कोटा तथा अन्य जिलों में अपने परिवार के साथ मजदूरी करने जाते थे जिससे उनका साल भर के लिए जीवन यापन करने हेतु मात्र राशन-पानी की ही व्यवस्था हो पाती थी। लेकिन आज मनरेगा ने मेढ़ बंधान एवं कूप निर्माण, भूमि सुधार जैसी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है।

इसमें एक बहुत बड़ी विसंगति है जो मध्य प्रदेश राज्य में आ रही है। जहां पर राज्य शासन द्वारा समय पर एम.आई.एस. न करने के कारण तकनीकी कारणों से केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त राशि जारी नहीं की जा सकती है। प्रदेश सरकार की इस गलती का खामियाजा मनरेगा के मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है

, इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में इस महत्वपूर्ण जीवन दायिनी योजना की समीक्षा की जावें तथा राज्य समय पर एम.आई.एस. न करें अथवा मनरेगा की राशि किसी अन्य योजना में उपयोग कर ले जैसाकि मध्य प्रदेश राज्य करता आ रहा है। ऐसे राज्यों में जिस प्रकार भारत सरकार के रेलवे, हवाई यातायात और दूरदर्शन जैसे विभाग, बिना राज्य सरकार के हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं। उसी प्रकार इस मनरेगा योजना के समुचित संचालन हेतु भी केन्द्र सरकार का अमला, ऐसे राज्यों में स्थापित किया जाना चाहिए जिससे इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ सीधे हमारे देश के मजदूर वर्ग को ही मिले और राज्य सरकारें केन्द्र शासन की ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं का दुरूपयोग न कर पाएं।